(c) and (d) : Yes, Sir. Government have already announced their decision to stop concessional import of foodgrains after end of 1971. Import of cotton and soyabean oil will however have to be continued for some years because of the large gap between indigenous production of cotton and edible oils and the growing needs of the economy. Efforts are being made to increase the internal production of these commodities also as quickly as possible.

Statement

Main features of the PL. 480 Agreement signed on 1-4-1971 as amended.

A PL. 480 Agreement was signed with the US Govt. on 1st April, 1971 for the supply of Agricultural Commodities from that country. The value of this Agreement was slightly increased in May 1971 (from $ 150.00 million to $ 158.3 million). Taken with these additions, the agreement provides for an import of 15,70,000 tonnes of wheat, 250,000 Indian bales of cotton (200,000 bales in terms of US bales) and 102,000 tonnes of soyabean oil valued at $ 158.3 million. About 80% of the imports do not require rupee payment ; these will be under what are called Convertible Local Currency Credit Terms i. e. repayable in dollars over a period of 40 years, including a grace period of 10 years. The remaining 20% imports will be paid for in rupees, which rupees in turn have been earmarked for loan to Govt. of India 93%, and US uses 7%. Both the dollar and the rupees loan will carry interest at 2% during the first 10 years and 3% during the subsequent 30 years.

2. The Agreement further allows the U.S. to convert $ 7.5 million from the rupees earmarked for their uses into third country currencies for agricultural and educational exchange activities and for sale to U.S. tourists and citizens in India.

Mithila University

*146. SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI JAGANNATH MISHRA :
Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the executor of Darbhanga Raj has formally handed over the Raj Head Office, Library and Guest House worth above Rs. 2 crores to the Chief Minister of Bihar for the proposed Mithila University ; and

(b) if so, what are the obstructions in immediately starting the University ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA MEN UPAMANTRI) (SHRI D. P. YADAVA) ; (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटे सिक्कों की कमी

*147. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में छोटे सिक्कों की कमी अभी तक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 20 पैसे का सिक्का फाउन्टेन पैनों की निबें बनाने के उद्देश्य से पिघलाया जा रहा है और जिसकी कीमत बाजार में काफी बढ़ गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाई कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अनेक स्थानों से अभी तक शिकायतें आ रही हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्रों में अब भी सिक्कों की कमी है हालांकि स्थिति बराबर सुधरती जा रही है।

(ख) सिक्कों की कमी का मुख्य कारण यह लगता है कि 2 पैसे और ५ पैसे के मूल्य के तांबे-निकल के सिक्कों का धातु-मूल्य उनके अंकित मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाने के कारण ये सिक्के चलन से हटा लिये गये है। इन्हीं मूल्य-वर्गों के एल्यूमिनियम- मैंगनेशियम के सिक्के, जो क्रमश: 1965 और 1967 से चलन में लाये गये थे, स्पष्टत: पूरी तरह से तांबे-निकल के उन सिक्कों का स्थान नहीं ले पाये जो चलन से हटा लिये गये है। इस कमी की हालत और खराब होने का कारण सिक्कों की जमाखोरी है, जो ऐसी स्थितियों में एक सामान्य बात है।

(ग) कुछ राज्यों के उद्योग-निदेशकों द्वारा की गई जांच से समाचार-पत्रों में छपे उन समाचारों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती कि फाउंटेन पैन की निबें बनाने के लिए 20 पैसे के सिक्के गलाये जा रहे हैं। इसके अलावा, एल्यूमिनियम-कांसे के 20 पैसे के सिक्के का धातु मूल्य केवल 7 पैसे हैं जिसके कारण निबें तैयार करने के लिए इसे कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करने में घाटा ही रहेगा।

(घ) सरकार सिक्कों को गलाने की क्रिया को कानून द्वारा अपराध घोषित करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है किन्तु जो कमी पहले ही हो चुकी हैं उसे टकसालों में पहले से अधिक उत्पादन द्वारा सिक्कों की सप्लाई बढ़ाकर ही दूर किया जा सकता है। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें टकसालों में उत्पादन वृद्धि करने के लिए उठाये गये कदमों तथा अन्य विचाराधीन कदमों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

हैदराबाद और अलीपुर की टकसालों में अक्टूबर/नवम्बर 1970 से प्रति सप्ताह 50 घन्टे के हिसाब से काम शुरु कर दिया गया जबकि इससे पहले केवल 48 घण्टे प्रति सप्ताह काम होता था। बम्बई की टकसाल में प्रतिदिन 9-9 घण्टे की दो पारियां शुरू की गयीं और जनवरी 1971 से अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहक योजना भी शुरू कर दी गई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप टकसालों में दैनिक उत्पादन का औसत 18 लाख सिक्कों से बढ़ कर 35 लाख सिक्के हो गया है। टकसालों से हाल में प्राप्त उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन की गति में तेजी आई है और तीनों टकसालों के दैनिक उत्पादन का औसत अब 50 लाख सिक्कों से भी अधिक हो गया है। सरकार का इरादा इस उत्पादन को 70 लाख सिक्के प्रतिदिन तक बढ़ाने का है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने बम्बई की टकसाल में, 400 अतिरिक्त औद्योगिक कामगरों की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी है ताकि सिक्कों के दैनिक उत्पादन के वर्तमान स्तर में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि अलीपुर टकसाल म 10 घण्टे की वर्तमान पारी के स्थान पर 9 9 घंटे की दो पारियां शुरू कर दी जायें और इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए श्रमिक संघ के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। हैदराबाद टकसाल को एल्यूमिनियम निःसारित पट्टियों (एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड स्ट्रिप) के प्रयोग की अनुमति दे दी गयी है ताकि गलकुशित एल्यूमिनियम मैंगनेशियम सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के काम में बाधा न बन सके।